



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]
No. 174]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 1984/चैत्र 22, 1906
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 1984/CHAITRA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

आदेश

का. आ. 279(अ)/18कक/आईडीआरए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का. आ. 790(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा तथा संशोधित आदेश सं. का. आ. 734 (अ)/18कक/आईडीआरए/82, तारीख 12 अक्टूबर, 1982 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में संशोधित कॉन्टि काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 285(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी

सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 725(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 11 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अप्रैल, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकाहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध गुजरात राज्य वस्त्र निगम के अधीन 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

॥

[फा. सं. 3(1) 82-सी यू एस]

ए. पी. सरवम, संयुक्त सचिव

